वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी.18, वनभवन, सैक्टर–6, पचकूला, दूरभाष 0172.2563988, 2563861 E-mail : cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः–डी–तीन–9207/3095 दिनांकः– 30-01-2023

सेवामें

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषयः Diversion of 13.684 ha.. Forest land (closed under section 4 & 5 of PLPA 1900) in favour of Manav Rachna International Institute of Research and Studies along Badkhal – Surajkund road under Forest Division and District Faridbad.
Online Proposal No. FP/HR/SCH/41500/2019

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 9-HRC093/2020-CHAदिनांक 02.12.2022

उपरोक्त संदर्भाकिंत पत्र द्वारा मांगी गई सूचना आपको निम्नप्रकार से भेजी जाती हैः–

1	Detailed breakup of 13.684 ha of forest land has not been provided in the online proposal. An area of 0.19 ha has also been encroached by the user agency and the State Govt has not sent any reply in its compliance dated 30.11.2022. Hence, Complete proposal incorporating the details of entire area under the possession of the user agency needs to be submitted by the State	इस सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, फरीदाबाद द्वारा अपने पत्र क्रमांक 951 दिनांक 30.12.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि 0.19 है0 वन भूमि front boundary wall से बाहर है, वन विभाग की सुरक्षित वन पट्टी है जिसके दोनो तरफ हरे पौधे लगे हुए है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आने जाने के रास्ते के लिए उपयोग किया जाता है तथा उन द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा कोई भी पेड नहीं काटा जायेगा। वन भूमि के डाईवर्सन के पश्चात् यूज़र ऐजेन्सी द्वारा वन विभाग को वन भूमि के बदलें में देने के लिए 13.684 है0 + 0.19 है0 कुल 13.874 है0 से अधिक भूमि देने का प्रबन्ध किया है। अतः यह स्पष्ट है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा कुल 13.874 भूमि है0 का प्रयोग किया जा रहा है।

2	Examination of Google Satellite Imagery revealed other similar construction in the area. The State Govt may, therefore, clarify if this is the isolated case or there are other similarly placed proposals. Detail of the same should be provided	प्रस्तावित स्थल के साथ लगते हुए वन क्षेत्र पर प्रपोजल नं0 FP/HR/SCH/41656/2019 एम0वी0एन0 स्कूल तथा FP/HR/SCH/49691/2019 अरावली इन्टरनेशल स्कूल स्थापित है, जोकि शैक्षणिक संस्थान है। जिनका एफ0सी0ए0 1980 के तहत प्रस्ताव उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के अन्य प्रस्ताव जोकि सैक्शन 4 व 5 ऑफ पी0एल0पी0ए0 के वन विभाग को प्राप्त हुए है। (फरीदाबाद जिले से सम्बन्धित सूचि अनुलग्न 'क' में संलग्न है)
3	Detail of Forest Offence Report booked by the DFO and its current status may be provided.	मानव रचना इन्टरनैशनल स्कूल के विरूद्ध चाक की गई एफ0ओ0आर0 का विवरण साथ संलग्न है। दर्ज की गई एफ0ओ0आर0 के सम्बन्ध में पर्यावरण न्यायालय में विचाराधीन/ आगामी आदेशों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति अनुलग्न 'ख' संलग्न है ।
4	Nodal Officer (FCA), in Part-IV, has also mentioned that extant proposal has been submitted as per the recommendation made by the CEC in IA No. 828 where CEC recommended that areas notified under section 4 and or 5 of the PLP Act including areas for which the notification have expired, areas planted under Aravalli afforestation project and other Plan/Non-Plan scheme of the Centre/State Government may also be treated as prohibited zone for colonization, construction of farm houses and other construction activities. Such activities in prohibited zone should be permissible only of found in public interests and after obtaining permission from Hon'ble Court. However, Hon'ble Supreme Court in its order dated 22.07.2022 directed that ".....If such non-forest use is permitted in accordance with Section 2 of the 1980 Forest Act, to that extent, the restrictions imposed by the special orders under Section 4 of PLPA will not apply in view of the language used in the opening part of Section 2 of the 1980 Forest Act"..... Therefore, a clarification is needed on the recommendation of the Nodal Officer made in Part-IV	The user agency has submitted application for diversion of said deemed forest land, falling under section 4 & 5 of PLPA 1900 under forest conservation ACT 1980. Further decision in this regard is to be taken by MoEF & CC, GOI as per the advice of CEC, directions of Hon''ble Supreme Court dated 21-07-2022 in Civil Appeal No. 10294 of 2013 Narinder Singh Vs Divesh Bhutani.
5	Examination of sites proposed for CA reveals that CA has been proposed in two isolated patches	यूजर ऐजेंसी द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतू 14.13 है0 भूमि का प्रबन्ध किया गया

	involving areas of 11.33 ha and 2.05 ha. As per extant guidelines, the minimum acceptable area of non-forest land identified for CA is 5 ha. Since the patches are isolated i.e. not contiguous to forest land, NFL of 2.05 needs to be changed to suitable location.	है, जिसके परचेज एग्रीमेन्ट की प्रति ऑनलाईन के0एम0एल0 फॉरमेट ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। क्रय अनुबंध पत्र अुनसार येजर ऐजेन्सी द्वारा 14.13 है0 भूमि का एक ही स्थान पर पौधारोपण हेतू प्रस्ताव दिया गया है।
6	Misleading details of alternative has been provided in the proposal i.e. in the online field pertaining to alternative examined, the details of CA land has been provided. Moreover, relevancy of the same has not been justified in view of the fact that intended use has already been constructed i.e. situation of fait accompli has been created. Hence, the details of alternatives examined, needs to be modified accordingly	यूजर ऐजेंसी द्वारा प्रति पूर्ति पौधारोपण के लिए 14.13 है0 भूमि का परचेज एग्रीमेन्ट की प्रति ऑनलाईन के0एम0एल0 फॉरमेट ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। यूजर ऐजेंसी द्वारा situation of fait accompli created के बारे उनके कार्यालय को अवगत करवाया है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा उपरोक्त भूमि का प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है। अतः अन्य विकल्प की सम्भावना न होने के कारण ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदन किया गया है। उल्घना हेतू उप वन संरक्षक फरीदाबाद द्वारा समय समय पर कार्यवाही करते हुए एफ0ओ0आर0 भी दर्ज करवाई गई है। प्रति अनुलग्न 'ग' संलग्न है।
7	Authorities in the Forest Department in their inspection report have mentioned that area proposed of diversion is barest minimum without justifying or indicating the supporting documents establishing the requirement as barest minimum. The detailed justification/documents needs to be given for justifying barest minimum	यूजर ऐजेन्सी ने AICTE Norms इस कार्यालय में जमा किए गए है जिसके अनुसार प्रस्तावित वन भूमि शिक्षण, खेलकूद, छात्रावास एवं पाठयोत्तर गतिविधि के लिए barest minimum है। प्रति अनुलग्नक 'घ' संलग्न है।

संलग्न / उपरोक्त

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला। 30/11/2023